भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6

2 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: सहकारी समितियों के विकास हेतु विस्तुत योजना।

6 श्री संजय सिंह:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने और, साथ ही, सहकारी समितियों के विकास के प्रोन्नयन हेतु सरकार की कोई नीति है अथवा नीति बनाने की योजनाए है;
(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सहकारी समितियों के बेहतर विकास हेतु केन्द्र तथा राज्यों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या कार्यक्षमता बढाने और रोजगार अवसर सृजित करने हेतु केन्द्र तथा राज्यों द्वारा कतिपय संयुक्त प्रयास किए गए है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी हाँ, महोदय। सरकार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से एक नई सहकारिता नीति तैयार कर रही है। प्रस्तावित नीति देश भर में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, मजबूत करने और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं और कार्यों के लिए रूपरेखा का काम करेगी।

(ग) से (ड.): सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करना चाहती है, और तदनुसार, सहकारी समितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ व्यापक परामर्श शुरू किया है। उदाहरण के लिए, प्रस्तावित नई सहकारिता नीति पर अब तक 10 मंत्रालयों और 6 राज्य सरकारों सहित 35 हितधारकों से सूचना और सुझाव प्राप्त हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के इन संयुक्त प्रयासों से प्रभावी नीतियों और योजनाओं का विकास हो सकता है और उनके सुचारू कार्यान्वयन से अंततः ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।

****